हर कोई अलग सोच रखना चाहता है, लेकिन अकेले खड़ा होना नहीं चाहता। सफल निवेशक बनने के लिए आपको निवेश शैली अपने व्यक्तित्व के अनुसार बनानी होगी।

माइकल बरी, अमरीकी हेज फंड मैनेजर



पत्रिका फाइनेंस

@बिजनेस & वेल्थ

शेयर बाजार		सोना	चांदी	रुपया
सेंसेक्स 72,382 (+473)	निफ्टी 22,556 (+134)	स्टैंडर्ड (24K) ₹1,51,500 (प्रति 10 ग्राम) (-500)	चांदी (999) ₹2,29,700 (प्रति किग्रा) (+1700)	₹96.30 (प्रति 1 डॉलर) (-0.05)

जीएसटी काउंसिल नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी सुधारों में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और कारोबारियों के लिए अनुपालन का बोझ घटाने पर केंद्र सरकार का जोर

कारोबारियों-ईकॉमर्स विक्रेताओं को राहत देने की तैयारी, सोने-चांदी के आयात पर सख्ती

नई दिल्ली @ पत्रिका. जीएसटी परिषद की बैठक अब 8 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में कारोबारियों को राहत देने के लिए व्यापक सुधारों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके तहत विवादों से निपटने में गिरफ्तारी के बजाय टैक्स वसूली, ब्याज और जुर्माने पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। ***नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी सुधारों में टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और अनुपालन का बोझ घटाने पर सरकार का जोर है।***

जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

1 सोना-चांदी : आयात पर टैक्स छूट होगी खत्म!

1 सोना-चांदी का आयात घटाने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जीएसटी परिषद सोना, चांदी और ***प्लेटिनम के आयात पर बैंकों को मिलने वाली टैक्स छूट खत्म कर सकती है।***

2 इन कीमती धातुओं के आयात पर सामान्य तौर पर 3% एकीकृत जीएसटी लगता है। लेकिन बैंकों और नामित एजेंसियों को इससे छूट मिली हुई है। ***यह छूट 2017 में कारोबार को आसान बनाने के लिए दी गई थी। उस समय इन धातुओं का आयात सीमित अधिकृत माध्यमों से होता था।***



3 छूट वापस लेने से कीमती धातुओं के एक्सचेंज, बैंकों और नामित एजेंसियों पर ***टैक्स कर के लिहाज से समान व्यवस्था लागू हो सकेगी।***

2 ई-कॉमर्स विक्रेताओं को ये राहतें संभव...

- छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को उन राज्यों में भी ***जीएसटी पंजीकरण की सुविधा देना शामिल है, जहां उनका अपना कार्यालय नहीं है।***
- ऐसे कारोबारी उन राज्यों में ई-कॉमर्स के ***गोदाम को अपना कारोबारी पता बता सकेंगे।*** इसके लिए किसी एक राज्य में उनकी वास्तविक कारोबारी मौजूदगी, भौतिक जांच और आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा।
- इससे 9.5 लाख छोटे विक्रेताओं को उन ***राज्यों में अलग कार्यालय खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां उनका माल रखा जाता है।*** इससे छोटे कारोबारियों को देशभर के बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।



3 आइटीसी का दावा कर सकेंगे नियोक्ता

नियोक्ता कर्मचारियों को बीमा कवर देने के लिए जो प्रीमियम चुकाते हैं, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा कर सकेंगे। व्यक्तियों की ओर से अपने या परिवार के लिए जीवन या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर जीएसटी से छूट है। हालांकि, जब संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए जीवन या स्वास्थ्य बीमा खरीदता है, तो उस पर टैक्स लगता है और अभी कंपनियां इस पर आइटीसी का दावा नहीं कर सकती हैं। अभी ऐसी सभी समूह बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी लगाया जाता है।

4 आसान पंजीकरण

जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। आवेदन भरते समय हर मार्गदर्शन मिलेगा। आवेदक को सिर्फ वही जानकारी भरने वाले हिस्से दिखेंगे जो उसके कारोबार से संबंधित हैं। जरूरी दस्तावेजों की सूची भी स्पष्ट दी जाएगी।

5 ऑडिट में राहत

कई राज्यों में कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए अलग-अलग राज्यों में ऑडिट के बजाय एक केंद्रीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाई जा सकती है। अभी कंपनियों को प्रत्येक राज्य में अलग-अलग ऑडिट का सामना करना पड़ता है।

6 ₹10,000 से कम की टैक्स मांग पर नोटिस नहीं

मुकदमा, टैक्स विभाग का प्रशासनिक बोझ घटाने के लिए 10,000 रुपए से कम की टैक्स मांग वाले मामलों में जीएसटी नोटिस जारी करने पर रोक लग सकती है। ऐसे मामले कुल मामलों की संख्या के करीब 20% हैं, लेकिन इनमें टैक्स की राशि बहुत कम होती है। यह व्यवस्था पुराने लंबित मामलों पर भी लागू हो सकती है, चाहे वे टैक्स निर्धारण या अपील के स्तर पर हों।

7 सही खरीदार का आइटीसी सुरक्षित रहेगा

परिषद ऐसे खरीदारों के आइटीसी को सुरक्षित रखने पर भी विचार कर सकती है, जिनके पास खरीद का वैध बिल है। यदि आपूर्ति श्रृंखला में पहले के किसी विक्रेता ने टैक्स नहीं चुकाया है, तो उसका बोझ सही खरीदार नहीं पड़ेगा।

8 माल ढुलाई में बार-बार जांच रोकने की तैयारी

खुफिया जानकारी के आधार पर मालवाहक वाहनों की जांच की व्यवस्था बनेगी। किसी वाहन को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की पहले मंजूरी जरूरी होगी। आम तौर पर जांच उसी राज्य में की जा सकेगी, जहां से माल रवाना हुआ।

9 टैक्स विवाद निपटाने के लिए साझा नियम

टैक्स डिमांड तय करने और उस पर फैसला लेने के लिए एक समान नियम बनाने पर भी विचार। इनमें नोटिस तैयार करने और पहुंचाने, सामान्य टैक्स की कमी को धोखाधड़ी से अलग करने, सुनवाई का मौका देने के नियम होंगे।

एसएमई आइपीओ बड़े मेनबोर्ड आइपीओ ने खड़ी की छोटी कंपनियों के लिए मुसीबत

0% रिटर्न... एसएमई कंपनियों के लिए अब बाजार से पूंजी जुटाना हुआ मुश्किल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. शेयर बाजार में जारी उठापटक के बीच वित्त वर्ष 2026-27 में बड़ी कंपनियों के आइपीओ में निवेशकों को मिल रहे शानदार रिटर्न ने छोटी कंपनियों के लिए शेयर बाजार से पूंजी जुटाने की राह मुश्किल कर दी है। निवेशक अब एसएमई (छोटे एवं मझोले उद्यम) के आइपीओ में पैसा लगाने से बच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस साल सूचीबद्ध हुए 151 एसएमई आईपीओ का मीडियन रिटर्न महज 1% रहा है। जुलाई-सितंबर के बीच लॉन्च एएमई आइपीओ का औसत रिटर्न सिर्फ 0.1% रहा। वहीं, मेनबोर्ड आईपीओ में औसत रिटर्न 27.1% और औसत लिस्टिंग गेन 14% से आधिक है। इतना ही नहीं 2026-27 की पहली छमाही में 70% मेनबोर्ड आइपीओ का औसत रिटर्न 55% से अधिक है। ऐसे में छोटी कंपनियों के लिए न केवल निवेशकों को आकर्षित करना चुनौती बन रहा है, बल्कि बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद शेयरों में टिकाऊ मांग बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है। इस साल एसएमई आइपीओ के जरिए कंपनियों ने रेकॉर्ड 2,079 करोड़ रुपए जुटाए है। पर इनमें से 70 शेयर अपने इश्यू प्राइस से नीचे कारोबार कर रहे हैं, जबकि 21 शेयरों की कीमत इश्यू प्राइस के मुकाबले 50% से ज्यादा गिर चुकी है। एसएमई के करीब 46% आइपीओ अपने इश्यू प्राइस से नीचे हैं। इसके उलट मेनबोर्ड में ऐसे शेयरों की हिस्सेदारी केवल 27% है। पिछले एक साल में एसएमई का प्रतिनिधित्व करने वाले निफ्टी इमर्ज इंडेक्स में 2.3% की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी आइपीओ इंडेक्स 12% चढ़ा है।

आगे की राह भी मुश्किल

जनवरी-जून में सूचीबद्ध 76 एसएमई आइपीओ में भी 47% शेयर ऑफर प्राइस से नीचे कारोबार कर रहे थे और मीडियन रिटर्न 5.1% रहा। लगातार कमजोर प्रदर्शन से एसएमई आइपीओ के प्रति निवेशकों की सावधानी बढ़ सकती है, जिससे छोटी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने की चुनौती और गहरी हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, मौजूदा आर्थिक माहौल और बाजार में अस्थिरता के कारण निवेशक एसएमई आइपीओ से दूरी बना रहे हैं। इसके विपरीत, मेनबोर्ड पर बड़ी कंपनियों के आइपीओ को लेकर निवेशकों में भरोसा अधिक है। उन्हें लगता है कि बड़ी कंपनियों में लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है। 2026-27 की दूसरी तिमाही में भी मेनबोर्ड आइपीओ की लंबी कतार है, जिससे एसएमई कंपनियों के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है।

01% से भी रह गया जुलाई से सितंबर के बीच लिस्ट हुए एसएमई आइपीओ का औसत रिटर्न, 45% आइपीओ अपने इश्यू प्राइस से भी नीचे

151 एसएमई कंपनियां लिस्ट हुईं 2026 में अब तक, जिनमें 46% यानी 70 कंपनियां इश्यू प्राइस से भी नीचे, ***मेनबोर्ड में 27% कंपनियां ही इश्यू प्राइस से नीचे***

जोरदार रिकवरी! क्या अब थम जाएगी बाजार की गिरावट?

मुंबई@पत्रिका. भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट का सिलसिला सोमवार को थम गया। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई थोड़ी नरमी के कारण बाजार में रौनक लौट आई। सेंसेक्स 473 अंक की तेजी के साथ 72,382 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 भी 0.60% की बढ़त लेकर 22,556 पर बंद हुआ। रेलीगेयर ब्रोकिंग और वेंचुरा के रिसर्च प्रमुखों ने कहा, यह तेजी पूरी तरह से बाजार का रुख बदलने वाली नहीं है, बल्कि इसे 'रिलीफ रैली' माना जाना चाहिए।

संकट 10% को-पेमेंट लागू करने पर विचार

क्या बीमा क्लेम की 10% राशि अपनी जेब से देनी होगी?

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

■ **1 जनवरी 2027** से 10% को-पेमेंट चार्ज लागू करने का जीआइसी का प्रस्ताव, ***पर इरडा से मंजूरी मिलना मुश्किल***

नई दिल्ली. हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले ग्राहकों के 1 जनवरी 2027 से बड़ा झटका लग सकता है। नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां रिटेल हेल्थ पॉलिसियों में 10% को-पेमेंट लागू करने पर विचार कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि अस्पताल में भर्ती होने पर कुल मान्य खर्च का 10% हिस्सा मरीज को खुद अपनी जेब से देना पड़ सकता है। यानी 5 लाख रुपए के हेल्थ क्लेम पर 50 हजार रुपए ग्राहक को देने पड़ सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआइसी) इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। जीआइसी के मुताबिक, यह नियम बीमारी से लेकर दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर आने वाले सभी स्वीकृत खर्चों पर लागू होगा। जीआइसी के इस प्रस्ताव को बीमा नियामक इरडा से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पॉलिसीधारकों के लिए राहत की बात यह है इस प्रस्ताव को इरडा से मंजूरी मिलने की संभवना बेहद कम है।

बीमा कंपनियों का तर्क : बीमा कंपनियों का मानना है कि जब मरीजों के पास 100% बीमा कवर होता है, तो अस्पताल बेवजह के डायग्नोस्टिक टेस्ट, ज्यादा दिनों तक भर्ती रखने या महंगे कमरे की सलाह देकर बिल बढ़ा देते हैं। मरीज की 10% हिस्सेदारी रहने से वे खर्च के प्रति सतर्क रहेंगे। दूसरी ओर, पॉलिसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह विकल्प ग्राहकों पर छोड़ना चाहिए।

उत्तर पश्चिम रेलवे

संक्षिप्त अधिसूचना

अप्रेन्टिस प्रशिक्षण सूचना संख्या 04/2026 (NWR/AA)

(यह भर्ती केवल खिलाड़ियों के लिए है)

अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेन्टिशिप प्रशिक्षण सूचना संख्या 04/2026 के द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाले मण्डलो एवं वर्कशॉप ईकाईयों पर अप्रेन्टिसो के प्रशिक्षण के लिये चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

- **आवेदन करने की अंतिम तिथि:**– 06.11.2026 समय: 23.59 बजे तक
- **कुल स्लॉट्स:**– 2008
- **न्यूनतम योग्यतायें:**– 10वी कक्षा की परीक्षा या उसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत) कम से कम 50% अंकों के साथ + संबंधित ट्रेड में ITI।
- **आयु सीमा:**– दिनांक 06.11.2026 को 15 से 24 वर्ष (SC, ST, OBC, PH & Ex Serviceman के अभ्यार्थियों को नियमानुसार छूट देय)

विस्तृत अधिसूचना, पात्रता शर्तो हेतु कृपया रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर की वेबसाइट www.rrcjaipur.in का अवलोकन करें।

अध्यक्ष/रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर

/NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

1416-PH/26

फॉर्म-II

बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016। CIN: U42202DL2025GOI456212

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (2) के तहत)

1. **बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड,** जिसका पंजीकृत कार्यालय **बी–9, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016** में स्थित है, और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (1) के तहत केंद्रीय ऊर्जा नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष ट्रांसमिशन लाइनों, सब–स्टेशनों और अन्य संपत्तियों से संबंधित ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र0 सं0	लाइन/सब–स्टेशन (लोकेशन) का नाम	लाइन की लंबाई / क्षमता	कार्य पूर्ण करने का अनुमानित व्यय/ औसत मारेषण शुल्क	अनुसूची सीओडी	टिप्पणियां
1	2x125 MVAr बस रिएक्टर के साथ बाड़मेर ((बाड़मेर II सब–स्टेशन) के पास उपयुक्त स्थान पर 400/220 kV, 6x500 MVA उप–केंद्र की स्थापना **भविष्य के प्रावधान (वर्तमान योजना के दायरे को छोड़कर):** ➢ 400kV लाइन–बे (line bays) के साथ स्विच–योग्य लाइन रिएक्टर– 6 ➢ 400kV लाइन–बे – संख्या 4 ➢ बे के साथ–साथ 400kV बस रिएक्टर -सं0 1 ➢ बे के साथ 400/220kV ICT: संख्या 4 ➢ 220kV सेक्शनलाइजेशन बे: 2 सेट ➢ री एप्लीकेशन्स की कनेक्टिविटी के लिए 220kV लाइन बे – संख्या 5 ➢ 220kV सेक्शनलाइजेशन बे : 2 सेट ➢ 220kV BC (संख्या 2) और TBC (संख्या 2) ➢ 400kV लेवल पर 2 नंबर सिंक्रॉन यूनिट्स* के साथ 2 की संख्या में 400kV बे ➢ STATCOM (2±300MVAr, 4x125MVAr MSC, 2x125 MVAr MSR) के साथ 400kV बे (2 सं.) *(1 नंबर सिंक्रॉन यूनिट में +300MVAr/-200MVAr (न्यूनतम) का डायनामिक सपोर्ट और PCC पर 1200MVA (न्यूनतम) का शॉर्ट सर्किट योगदान शामिल है)	• बाड़मेर - II PS - AIS • 400/220kV 500MVA ICTs - संख्या 6 • 400kV ICT बे– संख्या 6 • 220kV ICT बे– संख्या 6 • 125MVAr बस रिएक्टर– संख्या 2 • 400kV बस रिएक्टर बे– संख्या 2 • 400kV लाइन बे–संख्या 4 (री इंटरकनेक्शन के लिए) • 220kV लाइन बे – संख्या 7 (री कनेक्टिविटी के लिए) • 220kV सेक्शनलाइजेशन बे: 1 सेट • 220kV BC (2 नंबर) और TBC (संख्या 2) • 400kV सेक्शनलाइजर बे – 1 सेट	रु0 32,443.25 मिलियन वार्षिक	48 महीने (23.09.2030)	
2	बाड़मेर-II पीएस पर 400kV फतेहगढ़-IV पीएस - बाड़मेर-I पीएस डी/सी लाइन दोनों सर्किट्स का LILO	• लाइन की लंबाई – 13 Km (LILO लंबाई – 13 Km) • 400kV लाइन बे-संख्या 4 (बाड़मेर-II पीएस एंड पर)			
3	बाड़मेर-II पीएस - बाड़मेर-I पीएस 400kV डी/सी लाइन (क्वाड)	• लाइन की लंबाई – 19Km • बाड़मेर-II पीएस पर 400kV लाइन बे - सं0 2 • बाड़मेर-I पीएस उप-केंद्र पर 400kV लाइन बे-सं0 2			
4	बाड़मेर-II उप–केंद्र के पास एक उपयुक्त स्थान पर 6000MW, ±800kV बाड़मेर-II (HVDC) [LCC] टर्मिनल स्टेशन (4x1500MW) की स्थापना	• HVDC टर्मिनल स्टेशन (±800kV, 3000MW (बाइपोल कॉन्फिगरेशन) - संख्या 2)		54 महीने (23.03.2031) (बाइपोल-1: 48 महीने (23.09.2030) बाइपोल-2: 54 महीने (23.03.2031))	
5	कलंब के दक्षिण में उपयुक्त स्थान पर 6000MW, ±800kV दक्षिण कलंब उप–केंद्र (HVDC) [LCC] टर्मिनल स्टेशन (4x1500MW) की स्थापना	• HVDC टर्मिनल स्टेशन (±800kV, 3000MW (बाइपोल कॉन्फिगरेशन) - संख्या 2)			
6	बाड़मेर-II (HVDC) और दक्षिण कलंब (HVDC) के बीच ±800kV HVDC बाइपोल लाइन (हेक्सा लैपविंग) (पेरेलल डेडिकेटेड मेटालिक रिटर्न के साथ) (जिससे 6000MW बिजली भेजी जा सके) [100% रिवर्स पावर क्षमता के साथ]	• लाइन की लंबाई – 975 Km		48 महीने (23.09.2030)	
7	दक्षिण कलंब उप–केंद्र का विस्तार# 4x1500MVA, 765/400kV ICTs (3 400kV और 765kV सेक्शन-II पर, और 1 400kV और 765kV सेक्शन-I पर) के साथ, और 2x330MVAR, 765kV बस रिएक्टर और 2x125MVAR, 420kV बस रिएक्टर सेक्शन-II पर। सेक्शन-II को WR में एक अलग नेटवर्क विस्तार योजना के तहत स्थापित किया जाएगा जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है।# (2x1500MW HVDC बाइपोल-I को 400kV सेक्शन-I पर और 2x1500MW HVDC बाइपोल-II को दक्षिण कलंब के 400kV सेक्शन-II पर टर्मिनेट किया जाएगा और 765kV बस सेक्शनलाइजर को सामान्यतः बंद रखा जाएगा तथा 400kV बस सेक्शनलाइजर को सामान्यतः खुला रखा जाएगा)	• 765/400kV 1500MVA ICTs - संख्या 4 • 765kV ICT बे - संख्या 4 • 400kV ICT बे - संख्या 4 • 330MVAr बस रिएक्टर सं0–2 बस सेक्शन II में) • 765kV बस रिएक्टर बे - सं0 2 (बस सेक्शन II में) • 125MVAr बस रिएक्टर - सं0 2 (बस सेक्शन II में) • 400kV बस रिएक्टर बे - सं0 2 (बस सेक्शन II में)		48 महीने (23.09.2030)	
8	बाड़मेर-II पीएस के 400kV स्तर पर 2 सिंक्रॉन यूनिट् (1 सिंक्रॉन यूनिट में +300 MVAr/-200 MVAr (न्यूनतम) की डायनेमिक सपोर्ट और पीसीसी पर 1200MVA (न्यूनतम) का शॉर्ट सर्किट योगदान शामिल है)	• सिंक्रॉन यूनिट्स - 2 संख्या • 400kV लाइन बे - 2 संख्या		48 महीने (23.09.2030)	

के दक्षिण कलंब उप–केंद्र की स्थापना जिसमें 2x1500MVA, 765/400kV ICTs with 2x330MVAR, 765 kV बस रिएक्टर और 2x125 MVAR, 420kV बस रिएक्टर शामिल हैं, साथ ही पुणे-III - बोईसर-II 765kV D/c लाइन का LILO (जिसका निर्माण वर्तमान में अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी M/s WRNES TPTL द्वारा किया जा रहा है)।

$ नेटवर्क विस्तार योजना: नए 765kV और 400kV बस सेक्शन-II और III का निर्माण 765kV सेक्शनलाईजेशन के 2 सेट और 400kV सेक्शनलाईजेशन के 2 सेट के साथ, सेक्शन-III पर 2x330MVAR, 765kV बस रिएक्टर और 2x125MVAR, 420kV बस रिएक्टर प्रस्तावित किया जा रहा है, साथ ही ICT ऑगमेंटेशन (3x1500 MVA, 765/400kV ICTs) बस सेक्शन-III में 765kV और 400kV स्तर दोनों पर, तथा बस सेक्शन-III से दक्षिण कलंब उप–केंद्र की डाउनस्ट्रीम 400kV लाइन्स के साथ, प्रभावी तिथि से 24 महीनों के कार्यान्वयन समय में। [400kV सेक्शनलाइजर सेक्शन-I और II के बीच और सेक्शन-II और III के बीच सामान्यतः खुले रहेंगे। इसके अलावा, 765kV सेक्शनलाइजर सेक्शन-I और II तथा II और III के बीच सामान्यतः बंद रखे जाएंगे। 400kV सेक्शनलाइजर आपातकालीन परिस्थितियों में बंद किए जा सकते हैं।]

2 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला संपूर्ण आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.powergrid.in/en/subsidiaries** पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आवेदन को कंपनी के कार्यालय में, जो कि C/o ED (Commercial & RC), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरी मंजिल, टॉवर–01, IRCON इंटरनेशनल टॉवर, प्लॉट नं. 16, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, सेक्टर–32, गुड़गांव–122003 में स्थित है, बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के परियोजना प्रभारी श्री आर. के. गुप्ता के पास, अथवा आयोग के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

3 किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव होने पर, अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर, उन्हें सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029, के पास प्रस्तुत किया जा सकता है। आपत्ति/सुझाव की एक प्रति आवेदनकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट को भी दी जाएगी।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 06.10.2026

परियोजना प्रभारी
बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

PG/CC/Notice-58(SPV)/Advt-78/26-27/centrum

एफडीआइ तो बंपर आया... लेकिन भारत में ठहरा कम

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. भारत में विदेशी निवेश ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में नया रेकॉर्ड बनाया है। अप्रैल-जून 2026 में देश में 30.66 अरब डॉलर का ग्रॉस एफडीआई आया, जो करीब 15 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले सबसे ज्यादा ग्रॉस एफडीआई 2020-21 की दूसरी तिमाही में आया था। लेकिन रेकॉर्ड विदेशी निवेश की तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इसमें से करीब 44 फीसदी रकम विदेशी निवेशकों ने डिविडेंड, रॉयल्टी और शेयर बेचकर वापस बाहर निकाल ली। वहीं, भारतीय कंपनियों के विदेश में निवेश करने से भी करीब 31 फीसदी के बराबर विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई। नतीजा यह रहा कि ग्रॉस एफडीआइ में से वास्तविक रूप से देश में बचा नेट एफडीआई 7.84 अरब डॉलर रहा। यह पांच साल का सबसे ऊंचा स्तर जरूर है, लेकिन ग्रॉस एफडीआइ का सिर्फ करीब 25 फीसदी है।

'डील ऐसे मुकाम पर जहां और रियायत देना मुश्किल'

नई दिल्ली@पत्रिका. भारत-अमरीका ट्रेड डील पर अनिश्चितता बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में 'म्यूनिख लीडर्स मीटिंग' में कहा, ट्रेड डील पर चल रही बातचीत ऐसे मोड़ पर आकर अटक गई है, जहां से आगे बढ़ना दोनों देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन दोनों पक्ष अब संभवतः एक ऐसे ठहराव के स्तर पर हैं, जहां न तो भारत और छूट देने को तैयार है, और न ही अमरीका। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने पहले ही पर्याप्त रास्ते खोले हैं। और रियायतें देना देशहित के खिलाफ हो सकता है।

सभी समस्याओं के लिए अमरीका दोषी नहीं : जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, वैश्विक व्यापार के सामने मौजूद सभी समस्याओं के लिए ट्रंप की नीतियां एक कारण है, पर इसके लिए सिर्फ अमरीका को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उन्होंने कहा, हम व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए अमरीका को दोषी नहीं ठहरा सकते।

BDA BIKANER

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांकः-बी.वि.प्रा./जोन/2026-27/24773795 दिनांकः 29.09.2026

विज्ञप्ति

प्राधिकरण की व्यापार नगर आवासीय योजना, एन.आर.आई. आवासीय कॉलोनी, स्वर्ण जयन्ती टाऊनशीप आवासीय योजना खसरा नं. 153 (हरोलाई हनुमान जी), पुरानी जैल परिसर व्यवसायिक कम आवासीय योजना, करणी नगर आवासीय योजनाओं में भूखण्डों की भव्य नीलामी दिनांक 07.10.2026 से दिनांक 14.10.2026 तक

क्र. सं.	योजना का नाम	क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	अमानत राशि	प्रारम्भिक बोली दर (प्रति वर्गफीट)	भूखण्डों की संख्या
1.	व्यापार नगर आवासीय योजना	1225	103145.00	4210.00	09
2.	एन.आर.आई. आवासीय कॉलोनी (कॉर्नर)	2800	162960.00	2910.00	03
3.	एन.आर.आई. आवासीय कॉलोनी (कॉर्नर)	1750	101850.00	2910.00	01
4.	एन.आर.आई. कॉलोनी	1750	91350.00	2610.00	01
5.	स्वर्ण जयन्ती टाऊनशीप हरोलाई हनुमान जी	800	56160.00	3510.00	14
6.	पुरानी जैल परिसर व्यवसायिक कम आवासीय योजना (कॉर्नर)	1452.60	735887.00	25330.00	01
7.	पुरानी जैल परिसर व्यवसायिक कम आवासीय योजना (कॉर्नर)	1839.96	932124.00	25330.00	01
9.	पुरानी जैल परिसर व्यवसायिक कम आवासीय योजना (कॉर्नर)	1864.17	944389.00	25330.00	01
10.	पुरानी जैल परिसर व्यवसायिक कम आवासीय योजना	1452.60	687370.00	23660.00	06
11.	करणी नगर आवासीय योजना	1225	198940.00	8120.00	03
12.	करणी नगर आवासीय योजना	1920	311808.00	8120.00	02
				कुल भूखण्ड	42

नोटः-

1. ई-नीलामी (ऑनलाईन) से सम्बंधित जानकारी एवं मानचित्र आदि कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबाईट नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी https://udhonline.rajasthan.gov.in/Uploads/UDHe-auction.pdf एवं https://udhonline.rajasthan.gov.in/ Portal/AuctionListNew पर भी उपलब्ध है। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना SSO ID – Urban Services - Profile व Refund Account बनाना सुनिश्चित करें।
2. अमानत राशि ई-नीलामी पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवाने की प्रारम्भिक दिनांक 05.10.2026 समय 11:00 AM से 13.10.2026 11:59 PM तक एवं ऑनलाईन बोली लगाने की प्रारम्भिक दिनांक 07.10.2026 समय 11:00 AM से 14.10.2026 11:00 AM तक।

सचिव
बीकानेर विकास प्राधिकरण
बीकानेर

पत्रिका She NEWS

कॉटेज इंडस्ट्री में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

'कॉटेजकोर' के जरिए पाएं सुकून और एक नई पहचान

9 से 5 की नौकरी से आगे अपने हुनर की दुनिया चुन रही हैं महिलाएं।



पत्रिका फीचर नेटवर्क
patrika.com

क ई महिलाएं अपने जीवन को नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। वे ऐसे कामों की ओर बढ़ रही हैं, जहां वे रचनात्मकता, पसंद और हुनर को पहचान दे सकें। 'कॉटेजकोर' इसी सोच का हिस्सा है। घर पर बेकिंग, गार्डनिंग, हस्तनिर्मित उत्पाद, प्राकृतिक चीजों से जुड़े छोटे व्यवसाय और होम बेस्ड काम कमाई-आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री यानी ऐसे छोटे उद्योग, जिन्हें कम पूंजी और सीमित संसाधनों के साथ घर या छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है।

खुद से जुड़ने का एक अच्छा तरीका

'कॉटेजकोर' की खास बात है कि यह रोजमर्रा के कामों को खुशी का हिस्सा बना देता है। कॉटेजकोर महिलाओं को अपनी रचनात्मकता और पसंद के लिए समय निकालने का अवसर देता है। बागवानी, खाना बनाना, सिलाई-कढ़ाई, पेंटिंग या घर सजाने जैसे कामों को यह केवल घरेलू जिम्मेदारी नहीं बल्कि कला और आत्म-अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। कोई भी यह जीवनशैली अपना सकता है।

क्या हैं इसके मायने?

कई महिलाओं ने 'कॉटेजकोर' लाइफस्टाइल को सिर्फ पसंद नहीं बल्कि अपनी नई पहचान बनाने का रास्ता बनाया है। किसी ने नौकरी छोड़कर घर की रसोई से होम बेकरी शुरू की, तो किसी ने पौधों की देखभाल के शौक को नर्सरी के छोटे व्यवसाय में बदल दिया। वहीं कुछ ने अपने हुनर से हस्तनिर्मित सजावटी सामान, कैंडल, प्राकृतिक उत्पाद और होम डेकोर आइटम बनाकर अपना कारोबार खड़ा किया। 'कॉटेजकोर' का मतलब है आधुनिक जीवन के बीच सादगी और संतुलन के लिए जगह बनाई जाए। 'कॉटेजकोर' भागदौड़ से थोड़ा दूर जाकर सादगी, प्रकृति और अपने हाथों से किए जाने वाले कामों में खुशी तलाशने वाली जीवनशैली है। यह आपको कॉटेज इंडस्ट्री से भी जोड़ सकती है। आत्मनिर्भर होकर एक नई राह और दिशा पकड़ी जा सकती है।

नई दिशा

आत्मनिर्भरता की मुस्कान

कभी करती थीं दिहाड़ी मजदूरी अब रूबी चला रहीं अपनी दुकान



क भी घर का खर्च चलाना और बच्चों की पढ़ाई जारी रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। आर्थिक परेशानियों के बीच उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार संभाला, लेकिन आज वही बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड स्थित करणपुरा गांव की रहने वाली रूबी देवी अपने गांव में एक किराना दुकान चला रही हैं। सतत आजीविका योजना और PM-AJAY योजना के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता मिला और वे आगे बढ़ गईं।

ऐसे हुई शुरुआत

रूबी की जिंदगी में बदलाव तब आया, जब उन्हें सतत आजीविका योजना के तहत चुना गया। संगम जीविका महिला ग्राम संगठन के माध्यम से उन्हें किराना दुकान शुरू करने के लिए सहायता मिली। व्यवसाय शुरू करने से पहले रूबी को प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं संगम जीविका ग्राम संगठन से जुड़ने के बाद वे सामाजिक-सामुदायिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। वे अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाहती हैं।

लोग कहते हैं रूबी दीदी, मिल रहा सम्मान

रूबी की कहानी आर्थिक बदलाव तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक सम्मान से भी जुड़ी है। पहले उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में जगह नहीं मिलती थी। आज आत्मविश्वास और सफल व्यवसाय के कारण उनकी पहचान बदल गई है। गांव के लोग उन्हें सम्मान से रूबी दीदी कहकर सामाजिक कार्यक्रमों में बुलाते हैं।

आप भी कर सकती हैं शुरुआत: PM-AJAY के जरिए अनुसूचित जाति समुदायों के लिए स्थायी आजीविका, बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने हाल में PM-AJAY मोबाइल ऐप और पोर्टल शुरू किया है।

फिट एंड फाइन

आप हैं 'बिजी बी वुमन' तो ऐसा करें



बि जी बी वुमन (Busy Bee women) ऐसी महिलाओं को कहा जा सकता है, जो किसी न किसी काम में व्यस्त-सक्रिय रहती हैं। लेकिन लगातार काम करते रहना ही संतुलित जीवन नहीं है। एक बिजी बी वुमन की जिंदगी में थोड़ा-सा सोशल बटरफ्लाई (Social Butterfly) वाला रंग जरूरी है। यानी लोगों से जुड़ना, बातचीत करना, दोस्ती निभाना और अपने आसपास सकारात्मक रिश्तों का माहौल बनाना। फिटनेस पर ध्यान दें।

बी बैलेंस फॉर्मूला
बॉडी: शरीर को मजबूत बनाएं
ब्रेथ: सांस-मन को संभालें
ब्रेक: खुद के लिए ब्रेक लें

'बिजी बी वुमन' कैसे बन सकती हैं 'सोशल बटरफ्लाई'?

आप छोटे कदमों से शुरुआत करें। सप्ताह में कुछ समय दोस्तों या परिवार के लिए निकालें। अपनी पसंद की सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लें। किसी हॉबी ग्रुप से जुड़ें। पड़ोस या समुदाय के लोगों से बातचीत बढ़ाएं। बस काम और जिम्मेदारियों तक ही खुद को सीमित न रखें।

बिजी नहीं प्रोडक्टिव बनें-

सही दिशा में काम करना जरूरी है। जरूरी काम पहले करें। हर काम को खुद करने की आदत कम करें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। मेमोरी मेकर भी बनें। काम पूरे करने के साथ ही जिंदगी के खूबसूरत पल भी संजोएं।

किचन में कार्य करते समय खाना बनाने से लेकर उसकी साफ-सफाई तक में काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके पास कुछ किचन सॉल्यूशन हों तो आपके नाम व अपनी फोटो सहित हमें वॉट्सऐप नंबर ***9057531584*** पर भेजें। शी न्यूज पेज पर इन्हें प्रकाशित किया जाएगा। फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें।

पत्रिका शी न्यूज हमसे जुड़ें

पिण्डवाड़ा में दो मिनी ट्रकों की बैटरियां चुरा ले गए चोर

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com



ऑफिस के बाहर खड़े मीनी ट्रक से बैट्री चुराते हुए दिखाई देते चोर।

पिण्डवाड़ा . शहर के सिरोही रोड स्थित एसडीएम कार्यालय के सामने एक कूरियर कार्यालय के बाहर खड़े दो मिनी ट्रकों से अज्ञात चोर रविवार देर रात बैटरियां चुरा ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर कार में सवार होकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनेश कुमार रावल ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे उन्होंने रोजाना की तरह दोनों मिनी ट्रक और एक पिकअप कार्यालय के बाहर खड़े किए और घर चले गए। सोमवार सुबह करीब 8 बजे उनके पुत्र विक्रम रावल और कर्मचारी प्रहलाद सिंह कार्यालय पहुंचे। मिनी ट्रक चालू करने का प्रयास किया तो दोनों स्टार्ट नहीं हुए। वायर की जांच करने पर बैटरियां गायब थीं। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर रविवार देर रात करीब 2.30 बजे एक कार कार्यालय के बाहर आकर रुकती दिखाई दी। कार से दो युवक उतरे और कुछ ही देर में दोनों मिनी ट्रकों की बैटरियां निकालकर कार में सवार होकर फरार हो गए।

फुटेज के आधार पर जांच

पीड़ित ने पिण्डवाड़ा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और संदिग्ध युवकों की पहचान के प्रयास शुरू किए हैं।

फुटेज के आधार पर आरोपियों के सुराग जुटाए जा रहे हैं। पुलिस टीम जांच में जुटी है। -**चेलसिंह,** थानाधिकारी पिण्डवाड़ा

बस खराब होने से फंसे हरियाणा के विद्यार्थी, छात्राओं की तबीयत बिगड़ी

सरूपगंज पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, विद्यार्थियों के लिए भोजन-पानी की कराई व्यवस्था

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

स्वरूपगंज . थाना क्षेत्र के कोदरा बांध के पास रविवार देर रात हरियाणा के विद्यार्थियों से भरी स्कूल बस तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गई। इस दौरान तीन छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर मौके पर पहुंची स्वरूपगंज पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही थाने से श्रवण कुमार मौके पर पहुंचे और तीनों छात्राओं महक, सृष्टि देव और शाल्या को पुलिस वाहन से स्वरूपगंज सीएचसी पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उपचार किया। उपचार के बाद तीनों की स्थिति सामान्य बताई गई। देर रात सुनसान इलाके में बस खराब होने से विद्यार्थियों के सामने भोजन और पानी की समस्या भी खड़ी हो गई। पुलिस ने तत्काल विद्यार्थियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कराई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और ग्रामीणों ने सराहना की।

पत्रिका
विस्तृत खबरों और फोटोग्राफ्स के लिए देखें...
patrika.com

सिरोही में 7वीं कक्षा की छात्रा फंदे पर झूली, मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस

पत्रिका क्राइम रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com



सिरोही. शव को मोर्चरी लेकर जाते समाजसेवी व अन्य।

सिरोही . सिरोही. शहर के डाबी लाइन में सोमवार दोपहर 13 वर्षीय 7वीं कक्षा की छात्रा फंदे से झूल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। थानाधिकारी कैलाशदान ने बताया कि झूपाघाट हाल डाबी लाइन निवासी रमेश कुमार की 13 वर्षीय बेटी याना कुमारी फंदे पर झूल गई। घटना के दौरान रमेश और उसकी पत्नी काम पर और बेटा स्कूल गया था। बेटी घर मौजूद थी। जब दोपहर में मां काम से लौटी तो याना फंदे से झूलते दिखी। सूचना पर पहुंची पुलिस मौत के कारण तलाशने में जुट गई।

मां ने स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तो बोली- शूज धोने हैं

सहायक उपनिरीक्षक सत्येंद्र रत्नू ने बताया कि परिजनों के अनुसार सुबह मां ने बेटी से स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आज शूज धोने हैं, इसलिए स्कूल नहीं गई। इसके बाद पिता पेंट का काम करने चले गए, जबकि मां भी अपने काम से बाहर चली गई। दोपहर में मां घर लौटी तो बेटी फंदे से झूलती मिली। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है।

बलात्कार प्रकरण में वांछित आरोपी गिरफ्तार

सिरोही @ पत्रिका. स्वरूपगंज पुलिस ने बलात्कार के प्रकरण में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी सहायता व मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी को दस्तयाब किया। पूछताछ के बाद उसे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता की रिपोर्ट पर 17 सितंबर को प्रकरण दर्ज किया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी उसे मोटरसाइकिल से धनारी ले गया और करीब सात दिन तक उसकी इच्छा के विरुद्ध रेप किया। पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है।

पाली पत्रिका फेसबुक पेज
जुड़ें, पढ़ें और आगे बढ़ें
हर पल की खबर
facebook.com/pali.patrika
visit, like and share



फॉर्म-II
बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बी–9, कुतुब इंस्टीटूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016 | CIN: U42202DL2025GOI456212

सूचना
(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (2) के तहत)

1. **बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड,** जिसका पंजीकृत कार्यालय **बी–9, कुतुब इंस्टिटूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016** में स्थित है, और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (1) के तहत केंद्रीय ऊर्जा नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष ट्रांसमिशन लाइनों, सब–स्टेशनों और अन्य संपत्तियों से संबंधित ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र0 सं0	लाइन/सब–स्टेशन (लोकेशन) का नाम	लाइन की लंबाई / क्षमता	कार्य पूर्ण करने का अनुमानित व्यय/ औसत पारेषण शुल्क	अनुसूची सीओडी	टिप्पणियाँ
1	2x125 MVAr बस रिएक्टर के साथ बाड़मेर (बाड़मेर II सब–स्टेशन) के पास उपयुक्त स्थान पर 400/220 kV, 6x500 MVA उप–केंद्र की स्थापना **भविष्य के प्रावधान (वर्तमान योजना के दायरे को छोड़कर):** ➢ 400kV लाइन–बे (line bays) के साथ स्विच–योग्य लाइन रिएक्टर– 6 ➢ 400kV लाइन–बे – संख्या 4 ➢ बे के साथ–साथ 400kV बस रिएक्टर -सं0 1 ➢ बे के साथ 400/220kV ICT: संख्या 4 ➢ 220kV सेक्शनलाइजेशन बे: 2 सेट ➢ री एन्लीकेशन्स की कनेक्टिविटी के लिए 220kV लाइन बे – संख्या 5 ➢ 220kV सेक्शनलाइजेशन बे : 2 सेट ➢ 220kV BC (संख्या 2) और TBC (संख्या 2) ➢ 400kV लेवल पर 2 नंबर सिंक्रॉन यूनिट्स* के साथ 2 की संख्या में 400kV बे ➢ STATCOM (2±300MVAr, 4x125MVAr MSC, 2x125 MVAr MSR) के साथ 400kV बे (2 सं.) *(1 नंबर सिंक्रॉन यूनिट में +300MVAr/-200MVAr (न्यूनतम) का डायनामिक सपोर्ट और PCC पर 1200MVA (न्यूनतम) का शॉर्ट सर्किट योगदान शामिल है)	**बाड़मेर - II PS - AIS** • 400/220kV 500MVA ICTs - संख्या 6 • 400kV ICT बे– संख्या 6 • 220kV ICT बे– संख्या 6 • 125MVAr बस रिएक्टर– संख्या 2 • 400kV बस रिएक्टर बे– संख्या 2 • 400kV लाइन बे–संख्या 4 (री इंटरकनेक्शन के लिए) • 220kV लाइन बे – संख्या 7 (री कनेक्टिविटी के लिए) • 220kV सेक्शनलाइजेशन बे: 1 सेट • 220kV BC (2 नंबर) और TBC (संख्या 2) • 400kV सेक्शनलाइजर बे – 1 सेट	रु0 32,443.25 मिलियन वार्षिक	48 महीने (23.09.2030)	
2	बाड़मेर-II पीएस पर 400kV फतेहगढ़-IV पीएस - बाड़मेर-I पीएस डी/सी लाइन दोनों सर्किट्स का LILO	• लाइन की लंबाई - 13 Km (LILO लंबाई - 13 Km) • 400kV लाइन बे-संख्या 4 (बाड़मेर-II पीएस एंड पर)			
3	बाड़मेर-II पीएस - बाड़मेर-I पीएस 400kV डी/सी लाइन (क्वाड)	• लाइन की लंबाई - 19Km • बाड़मेर-II पीएस पर 400kV लाइन बे - सं0 2 • बाड़मेर-I पीएस उप-केंद्र पर 400kV लाइन बे-सं0 2			
4	बाड़मेर-II उप–केंद्र के पास एक उपयुक्त स्थान पर 6000MW, ±800kV बाड़मेर-II (HVDC) [LCC] टर्मिनल स्टेशन (4x1500MW) की स्थापना	• HVDC टर्मिनल स्टेशन (±800kV, 3000MW (बाइपोल कॉन्फिगरेशन) - संख्या 2)		54 महीने (23.03.2031) (बाइपोल-1: 48 महीने (23.09.2030) बाइपोल-2: 54 महीने (23.03.2031))	
5	कलंब के दक्षिण में उपयुक्त स्थान पर 6000MW, ±800kV दक्षिण कलंब उप–केंद्र (HVDC) [LCC] टर्मिनल स्टेशन (4x1500MW) की स्थापना	• HVDC टर्मिनल स्टेशन (±800kV, 3000MW (बाइपोल कॉन्फिगरेशन) - संख्या 2)			
6	बाड़मेर-II (HVDC) और दक्षिण कलंब (HVDC) के बीच ±800kV HVDC बाइपोल लाइन (हेक्सा लैपविंग) (पैरेलल डेडिकेटेड मेटालिक रिटर्न के साथ) (जिससे 6000MW बिजली भेजी जा सके) [100% रिवर्स पावर क्षमता के साथ]	• लाइन की लंबाई - 975 Km		48 महीने (23.09.2030)	
7	दक्षिण कलंब उप–केंद्र का विस्तार* 4x1500MVA, 765/400kV ICTs (3 400kV और 765kV सेक्शन-II पर, और 1 400kV और 765kV सेक्शन-I पर) के साथ, और 2x330MVAR, 765kV बस रिएक्टर और 2x125MVAR, 420kV बस रिएक्टर सेक्शन-II पर। सेक्शन-II को WR में एक अलग नेटवर्क विस्तार योजना के तहत स्थापित किया जाएगा जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है।# (2x1500MW HVDC बाइपोल-I को 400kV सेक्शन-I पर और 2x1500MW HVDC बाइपोल-II को दक्षिण कलंब के 400kV सेक्शन-II पर टर्मिनेट किया जाएगा और 765kV बस सेक्शनलाइजर को सामान्यतः बंद रखा जाएगा तथा 400kV बस सेक्शनलाइजर को सामान्यतः खुला रखा जाएगा)	• 765/400kV 1500MVA ICTs - संख्या 4 • 765kV ICT बे - संख्या 4 • 400kV ICT बे - संख्या 4 • 330MVAr बस रिएक्टर सं0–2 बस सेक्शन II में) • 765kV बस रिएक्टर बे - सं0 2 (बस सेक्शन II में) • 125MVAr बस रिएक्टर - सं0 2 (बस सेक्शन II में) • 400kV बस रिएक्टर बे - सं0 2 (बस सेक्शन II में)		48 महीने (23.09.2030)	
8	बाड़मेर-II पीएस के 400kV स्तर पर 2 सिंक्रॉन यूनिटें (1 सिंक्रॉन यूनिट में +300 MVAr/-200 MVAr (न्यूनतम) की डायनेमिक सपोर्ट और पीसीसी पर 1200MVA (न्यूनतम) का शॉर्ट सर्किट योगदान शामिल है)	• सिंक्रोन यूनिट्स - 2 संख्या • 400kV लाइन बे - 2 संख्या		48 महीने (23.09.2030)	

दक्षिण कलंब उप–केंद्र की स्थापना जिसमें 2x1500MVA, 765/400kV ICTs with 2x330MVAR, 765 kV बस रिएक्टर और 2x125 MVAR, 420kV बस रिएक्टर शामिल हैं, साथ ही पुणे-III - बोईसर-II 765kV D/c लाइन का LILO (जिसका निर्माण वर्तमान में अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी M/s WRNES TPTL द्वारा किया जा रहा है)।
$ नेटवर्क विस्तार योजना: नए 765kV और 400kV बस सेक्शन-II और III का निर्माण 765kV सेक्शनलाईजेशन बे: 2 सेट और 400kV सेक्शनलाईजेशन बे: 2 सेट के साथ, सेक्शन-III पर 2x330MVAR, 765kV बस रिएक्टर और 2x125MVAR, 420kV बस रिएक्टर प्रस्तावित किया जा रहा है, साथ ही ICT ऑगमेंटेशन (3x1500 MVA, 765/400kV ICTs) बस सेक्शन-III में 765kV और 400kV स्तर दोनों पर, तथा बस सेक्शन-III से दक्षिण कलंब उप–केंद्र की डाउनस्ट्रीम 400kV लाइन्स के साथ, प्रभावी तिथि से 24 महीनों के कार्यान्वयन समय में। [400kV सेक्शनलाइजर सेक्शन-I और II के बीच और सेक्शन-II और III के बीच सामान्यतः खुले रहेंगे। इसके अलावा, 765kV सेक्शनलाइजर सेक्शन-I और II तथा II और III के बीच सामान्यतः बंद रखे जाएंगे। 400kV सेक्शनलाइजर आपातकालीन परिस्थितियों में बंद किए जा सकते हैं।]

2 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला संपूर्ण आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.powergrid.in/en/subsidiaries** पर उपलब्ध हैं। आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आवेदन को कंपनी के कार्यालय में, जो कि C/o ED (Commercial & RC), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरी मंजिल, टॉवर–01, IRCON इंटरनेशनल टॉवर, प्लॉट नं. 16, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, सेक्टर–32, गुड़गांव–122003 में स्थित है, बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के परियोजना प्रभारी श्री आर. के. गुप्ता के पास, अथवा आयोग के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

3 किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव होने पर, अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर, उन्हें सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029, के पास प्रस्तुत किया जा सकता है। आपत्ति/सुझाव की एक प्रति आवेदनकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट को भी दी जाएगी।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 06.10.2026

परियोजना प्रभारी
बाड़मेर एचवीडीसी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

PG/CC/Notice-58(SPV)/Advt-78/26-27/centrum

जैकेट पेज से जारी...

एकतरफा...

ज्ञानेश का निलंबन, स्वतंत्र जांच व एसआइआर रद्द करने की मांग

राकेश सिंह व शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिकाओं में ईसी में एसआइआर पर एकतरफा निर्णय कर अवैध कार्यवाही करने के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने, न्यायिक निगरानी में मामले की स्वतंत्र जांच करवाने तथा एसआइआर को रद्द करने की प्रमुख मांगें की गई हैं।

विरोध प्रदर्शन को अनुमति पर जल्द सुनवाई को तैयार : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति देने के निर्देश दिए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस प्रदर्शन की अनुमति नहीं देती। सीजेआइ सूर्यकांत ने मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए और कहा कि देखा जाएगा कि पहले से तो ऐसे मामले लंबित नहीं हैं?

नाम हटाए जा रहे हैं तो एसआइआर का क्या मकसद: बॉम्बे हाईकोर्ट : बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने सोमवार को मौखिक टिप्पणी की कि यदि वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं तो एसआइआर का मकसद क्या है? जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जमसंदेकर की बेंच ने एक परिवार की याचिका पर यह टिप्पणी की जिसकी आपत्ति थी कि पता बदलने वाले फॉर्म आठ के बजाय एन्युमरेशन फॉर्म जमा नहीं करवाने के कारण उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। बेंच ने टिप्पणी की एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की बाध्यता क्यों जबकि पता बदलने के लिए फॉर्म-8 भरने का प्रावधान मौजूद है।

दुरुपयोग साबित : अब यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म-6 में गैरकानूनी और एकतरफा तरीके से बदलाव किया। यह एक और सबूत है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भाजपा की मदद की। -**राहुल गांधी,** नेता प्रतिपक्ष

स्वतंत्र होने का प्रमाण : ईसी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी करना लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के स्वतंत्र रूप से काम करने का प्रमाण मानते हैं। देश की सभी संस्थाएं बिना भय या दबाव के काम कर रही हैं। -**संबित पात्रा,** प्रवक्ता भाजपा

निजी...

आरजीएचएस पोर्टल के अनुसार, योजना में 13.61 लाख पंजीकृत लाभार्थी और 38.53 लाख परिवार के सदस्य यानी करीब 52.14 लाख लोग दर्ज हैं। प्रदेश में 2,663 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। योजना का मूल उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित पैकेज के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना है।

बोर्ड...

दीपावली से पहले एक माह में शहरों में सफाई, सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, नालियों, रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े सभी काम पूरे करने के लिए कहा है। बैठक में दस में से 9 महापौर शामिल हुए, इनमें बीकानेर से कांग्रेस के महापौर अनिल कल्ला मौजूद थे। अलवर की महापौर सुमनलता अग्रवाल वीसी के जरिए जुड़ीं।

पेज 1 का शेष...

निजी...

उक्त मरीज ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार में पदस्थ हैं। आरजीएचएस पोर्टल के अनुसार, योजना में 13.61 लाख पंजीकृत लाभार्थी और 38.53 लाख परिवार के सदस्य यानी करीब 52.14 लाख लोग दर्ज हैं। प्रदेश में 2,663 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। योजना का मूल उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित पैकेज के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना है।

लूनी नदी...

अधिकारियों ने बताया कि लूनी के एक सहायक नदी बांडी फुलाद के पास से निकलती है। यह 91 किलोमीटर का सफर तय कर धुधंड़ा के पास लाखड़ धुम्ब के निकट लूनी नदी में मिलती है। इसका ब्लू प्रिंट सिंचाई विभाग की ओर से तैयार किया जा चुका है। लोढ़ा ने एक दिन पहले रविवार को पाली की बांडी नदी क्षेत्र और ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया था।

हटाए जाएंगे अतिक्रमण : जस्टिस लोढ़ा ने नदियों के क्षेत्र में किए अतिक्रमण को हटाने को कहा। उन्होंने नदियों में होने वाले अवैध खनन को लेकर माइनिंग व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद जस्टिस लोढ़ा ने जवाई बांध के साथ जवाई नदी का बेड़ा के पास जायजा लिया। इसके बाद सुमेरपुर में भी जवाई नदी देखी। सेवाड़ी क्षेत्र में भी जायजा लिया। वहां से जस्टिस लोढ़ा सिरोही गए। वे सिरोही में उड़ा बांध के साथ नदियों का जायजा लेंगे। दौरे पर जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राहुल कुमार शर्मा, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता रिनेश सिंघवी, अधिशासी अभियंता शंकरलाल राठौड़, माइनिंग विभाग के विनीत गहलोत आदि अधिकारी साथ रहे।

प्रदूषण फैलाने पर सख्ती : पाली में नदी में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्ती की गई। बांडी नदी के आसपास औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित पानी का टैंकरों से परिवहन बंद किया गया। इस क्षेत्र की 48 इकाइयों की कंसेंट निरस्त की गई। बिजली कनेक्शन काटने के बाद से इकाइयां बंद हैं। प्रदूषित पानी बहाने पर पुनायता क्षेत्र में एक मकान को तोड़ा गया। कई जगह पर जमीन में बिछाई पाइप लाइन उखाड़ी गई। पाली शहर से आगे बांडी नदी पर नेहड़ा बांध बना है। इस बांध में प्रदूषित पानी का भराव होता है, जिसे हर बरसात में बहाया जाता रहा है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के निर्देश के कारण वह पानी अभी तक बांध में ही भरा है।

जिला...

बाद में फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत के बाद जांच हुई और दोनों लिपिकों को बर्खास्त कर दिया गया। जयपुर के बनीपार्क थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने दो लोगों की गिरफ्तारी की और इसी प्रकरण में जिला परिषद अलवर के एक और लिपिक राजेश यादव की गिरफ्तारी हुई। पुलिस जांच चल रही है। जांच के बीच ही यह ऑडियो सामने आया है।

8 माह..

यानी 79.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके विपरीत दुष्कर्म के मामलों में कमी दर्ज हुई है।

हर माह औसतन 3379 मामले दर्ज : इस साल जनवरी से अगस्त तक प्रदेश में महिला अत्याचार के 27 हजार 34 मामले दर्ज हुए हैं। आठ माह का औसत निकालें तो हर महीने 3 हजार 379 मामले सामने आए हैं। यही गति अगले चार माह में भी बनी रही तो साल के अंत तक करीब 40 हजार 500 मामले हो सकते हैं, जो महिला अपराध की दिशा में चिंताजनक स्थिति होगी।

छह...

निदेशालय की ओर से जारी नोटिस के साथ 678 चिकित्सकों की सूची संलग्न की गई है, जिसमें चिकित्सकों के नाम, पद, योग्यता, जन्मतिथि और आरपीएससी संबंधी विवरण दर्ज हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ राजस्थान सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन चिकित्सकों को लेकर भी सख्ती होगी, जिन्होंने सेवारत कोटे से पीजी पूरी की है। ऐसे मामलों में बांड की शर्तों के अनुसार राशि की वसूली के साथ राजस्थान मेडिकल काउंसिल से पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई भी होगी।